आत्मनिर्भरता और निवेश बढ़ाने पर जोर

रेल मंत्री वैष्णव ने पीएम की अपील विदेशी मुद्रा बचाएं पर अमल का अनुरोध किया

नयी दिल्ली, 11 मई केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की प्रधानमंत्री की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए सोमवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया संकट के बीच विजेता बनकर उभरेगा.

श्री वैष्णव ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि आज दो देशों के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया और भारत झेल रहा है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है. इसका कारण यह है कि हम ऊर्जा के अपने बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर हैं.

उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अमल का अनुरोध करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में गत 28 फरवरी से जारी संकट के कारण कई देशों में ईंधनों की कीमत काफी बढ़ गयी है लेकिन भारत ने उसे अबतक नियंत्रित रखा है.

उल्लेखनीय है कि श्री मोदी ने रविवार को लोगों से अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने, सोने की गैर-जरूरी खरीद न करने और ईंधन की बचत करने की अपील की थी.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'एक नागरिक के तौर पर हम हर उस खपत में कटौती कर सकते हैं जिसके लिए देश की विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है. साथ ही हम विदेश मुद्रा की कमाई बढ़ाने पर फोकस कर सकते हैं.'

> श्री वैष्णव ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो भारतीय अर्थव्यवस्था छह-आठ प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहेगी क्योंकि हमारा विकास लंबे समय तक कायम रहने वाला विकास है, हम इस संकट के बीच विजेता बनकर उभरेंगे. उन्होंने उद्योग जगत से सारी आशंकाओं को परे रखकर निवेश करने और भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने की अपील की.

50-30-20 फॉर्मूला से सैलरी मैनेज आसान

नयी दिल्ली, 11 मई आज के समय में ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों के लिए महीने के अंत तक सैलरी बचाना एक बड़ी समस्या बन गई है. किराया, बिजली बिल, बच्चों की फीस और ईएमआई जैसे खर्चों के कारण आमदनी तेजी से खत्म हो जाती है. ऐसे में वित्तीय विशेषज्ञ 50-30-20 फॉर्मूला को सबसे सरल और प्रभावी तरीका मानते हैं, जिससे लोग अपने खर्च, बचत और निवेश में बेहतर संतुलन बना सकते हैं. इस फॉर्मूले के अनुसार, सैलरी को तीन हिस्सों में बांटा जाता है. 50 प्रतिशत हिस्सा जरूरी खर्चों जैसे किराया, राशन, बिल और जरूरी ईएमआई के लिए रखा जाता है. 30 प्रतिशत हिस्सा जीवनशैली से जुड़े खर्चों जैसे बाहर खाना, घूमना, मनोरंजन और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर खर्च किया जाता है.

आरबीआई-ईसीबी ने सहयोग समझौता किया

बीआईएस बैठक में हस्ताक्षर किए गए

नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग पर जोर

मुंबई, 11 भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षा क्रिस्टीन लेगार्ड ने रविवार को केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग पर एक नये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये. इसमें दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग के लिए 2015 के समझौते का नवीनीकरण किया गया है.

रिजर्व बैंक की ओर से रविवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ये हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड के बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की बैठकों के दौरान किये गये. यह समझौता ज्ञापन 2015 के पिछले समझौता ज्ञापन का अद्यतन संस्करण है.

यह केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में दोनों संस्थानों के बीच नियमित सूचना आदान-प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है.

> भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के बीच हुआ नया समझौता (एमओयू) भारत और यूरोप के बीच आर्थिक और बैंकिंग सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह समझौता रविवार, 10 मई को स्विट्जरलैंड के बासेल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) की बैठक के दौरान किया गया, जिसमें आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा और ईसीबी की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने हस्ताक्षर किए. यह समझौता वर्ष 2015 में हुए पुराने एमओयू का अद्यतन रूप है, जिसका उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाना है.

एलपीजी ग्राहकों को कंपनियों का अलर्ट

नई दिल्ली, 11 मई देशभर में एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एचपी गैस, इंडेन और भारत गैस जैसी कंपनियों ने डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणाली लागू की है. हालांकि, इस नई व्यवस्था के साथ साइबर ठगी के मामले भी बढ़ने लगे हैं.

इसे देखते हुए गैस कंपनियों ने ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी अनजान संदेश या कॉल पर भरोसा कर ओटीपी साझा न करें.

गैस कंपनियों के अनुसार डीएसी एक तरह का सुरक्षा कोड या ओटीपी होता है, जो सिलेंडर बुकिंग के बाद ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. जब डिलीवरी कर्मचारी सिलेंडर लेकर ग्राहक के घर पहुंचता है, तभी यह कोड उससे साझा करना होता है. कोड का मिलान होने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाती है. इस व्यवस्था का उद्देश्य गलत डिलीवरी रोकना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और पारदर्शिता बढ़ाना है.

हाल ही में एचपी गैस ने अपने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के जरिए ग्राहकों को चेतावनी जारी की है. कंपनी ने बताया कि कई साइबर ठग नकली एलपीजी डिलीवरी संदेश भेजकर लोगों से ओटीपी और डीएसी कोड मांग रहे हैं. ऐसे मामलों में ग्राहकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

रिलायंस फाउंडेशन के प्रयासों से 3 हजार गांवों में बदला जीवन

ओआरएफ के साथ संयुक्त अध्ययन में दस वर्षों में आजीविका और ग्रामीण जीवन में सुधार का दावा

नई दिल्ली, 11 मई 2026: रिलायंस फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) ने ग्रामीण विकास पर दस वर्षों के कार्य का एक बड़ा अध्ययन जारी किया है. इस अध्ययन में देश के चार राज्यों के 3 हजार गांवों में हुए बदलावों का आकलन किया गया है.

अध्ययन में बताया गया है कि मजबूत स्थानीय संस्थाओं, लोगों की भागीदारी और मिलकर किए गए प्रयासों से गांवों में आजीविका और जीवन स्तर में सुधार हुआ है.

यह अध्ययन ओडिशा के बलांगीर, मध्य प्रदेश के मंडला, आंध्र प्रदेश के आदोनी और गुजरात के राधनपुर क्षेत्रों में किए गए कार्यों पर आधारित है. इसमें 2,100 से अधिक परिवारों के जीवन में आए बदलावों को समझा गया.

नई दिल्ली में आयोजित चर्चा में नीति विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विकास कार्यों से जुड़े लोगों ने आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण पर विचार-विमर्श किया.

ओआरएफ के उपाध्यक्ष डॉ. नीलांजन घोष ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करना जरूरी है. वहीं रिलायंस फाउंडेशन के मुख्य विकास अधिकारी सुदर्शन सुची ने कहा कि गांव तब आत्मनिर्भर बनते हैं जब लोग मिलकर समाधान तैयार करते हैं और स्थानीय संस्थाएं मजबूत होती हैं.

रिलायंस फाउंडेशन के ग्रामीण परिवर्तन कार्यक्रम प्रमुख अभिनव सेन ने कहा कि आंकड़ों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोगों की भागीदारी के जरिए ग्राम पंचायतों को और मजबूत बनाया जा सकता है.

> चर्चा में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया गया. रिलायंस फाउंडेशन ने बताया कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और खेल जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है तथा अब तक देशभर में 9.7 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच बना चुका है.

तेल उछला, शेयर बाजार दबाव में

सेंसेक्स 943 अंक टूटा, निफ्टी 23,900 के नीचे फिसला

मुंबई, 11 मई अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के चलते सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भारी दबाव में नजर आया.

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब एक प्रतिशत तक टूट गए, जबकि लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार करते दिखे. विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में बढ़ती अनिश्चितता और महंगे होते कच्चे तेल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 943 अंक यानी 1.22 प्रतिशत गिरकर 76,384 के इंट्राडे लो तक पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 280 अंक यानी 1.15 प्रतिशत टूटकर 23,897 पर कारोबार करता दिखा. बाजार में बिकवाली का दबाव इतना ज्यादा रहा कि लगभग सभी प्रमुख सेक्टर गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए. सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडेक्स में करीब तीन प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई.

एआई युग मानव संसाधन आधारित : अडानी

भारत को अपनी क्षमता खुद विकसित करनी होगी

एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लोग जरूरी

नयी दिल्ली, 11 मई अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोमवार को देश के विकास के लिए 'भारत' के लोगों को ध्यान में रखते हुए एआई के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इंटेलिजेंस युग सिर्फ सर्वरों और चिप्स की बजाय मानव संसाधनों में निवेश करके बनाया जा सकेगा.

श्री अडानी ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'इंटेलिजेंस युग केवल सर्वर, चिप्स और एल्गोरिदम से नहीं बनेगा. इसे इलेक्ट्रिशियन, तकनीशियन, ऑपरेटर, सुरक्षा अधिकारी, कूलिंग इंजीनियर, ग्रिड मैनेजर, डेटा सेंटर टीमें और लाखों युवा भारतीय मिलकर बनाएंगे, जो डिजिटल दुनिया के पीछे मौजूद भौतिक अवसंरचना का रखरखाव करेंगे.

उन्होंने कहा कि एआई का उद्देश्य भारत के लोगों की सेवा होना चाहिए. भविष्य में आजादी का मतलब क्षमता होगा और आजादी की अगली लड़ाई सीमा पर नहीं, बल्कि हमारे ग्रिडों में, डाटा सेंटरों में फैक्टरियों में, कक्षाओं में, प्रयोगशालाओं में और हमारे दिमाग के भीतर लड़ी जायेगी.

गुरुग्राम प्रॉपर्टी बाजार गरम

नई दिल्ली, 11 मई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कंपनियों में जारी छंटनी के बीच जहां दुबई जैसे बड़े रियल एस्टेट बाजार दबाव में हैं, वहीं गुरुग्राम का प्रॉपर्टी बाजार तेजी से उछाल दर्ज कर रहा है.

साल 2026 के पहले चार महीनों में ही गुरुग्राम ने करीब 27 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित कर बाजार विशेषज्ञों को चौंका दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर और नियामकीय पारदर्शिता ने गुरुग्राम को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का असर दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर साफ दिखाई दे रहा है. मार्च 2026 में दुबई रेजिडेंशियल वैल्यू इंडेक्स 5.9 प्रतिशत तक टूट गया, जबकि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में मासिक आधार पर 49 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कई इलाकों में संपत्तियों की कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत तक की कटौती करनी पड़ी है. अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भी अनिश्चित माहौल के चलते दुबई के बाजार से दूरी बनानी शुरू कर दी है.

सोना फिसला, चांदी में आई चमक

80 रुपए नीचे आया सोना

2378 रुपए उछली चांदी

नई दिल्ली, 11 मई. सोना 80 रुपये टूटकर ,चांदी के दाम में तेज उछाल देखने को मिला. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 80 रुपये टूटकर 1,52,443 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

वहीं चांदी 2,378 रुपये की तेजी के साथ 2,64,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना रहा. वैश्विक बाजार में सोना 0.74 प्रतिशत गिरकर 4,694 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जबकि चांदी 0.53 प्रतिशत मजबूत होकर 81.290 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निवेशकों की नजर फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता तथा वैश्विक आर्थिक संकेतकों पर बनी हुई है, जिसके कारण कीमती धातुओं की कीमतें सीमित दायरे में कारोबार कर सकती हैं.

देश के अलग-अलग शहरों में भी सोने की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिला. दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,39,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा.

समाचार विशेष

सिद्धरमैया की कुर्सी सुरक्षित हो गई

बेंगलुरु. चुनाव पांच राज्यों में हुए थे लेकिन इन चुनावों से कर्नाटक की राजनीति भी जुड़ी हुई थी. डीके शिवकुमार को असम में जिम्मेदारी मिली थी और कहा जा रहा था कि अगर असम में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो शिवकुमार का कद बढ़ेगा और वे कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ेंगे.

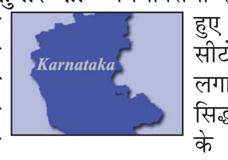

लेकिन कांग्रेस का असम में बहुत खराब प्रदर्शन हुआ. इसलिए शिवकुमार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. दूसरी खास बात यह है कि कर्नाटक की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. भाजपा ने इन सीटों पर पूरा जोर लगाया था. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन सीटों के चुनाव से अपनी प्रतिष्ठा जोड़ी थी. आमतौर पर उपचुनावों में मुख्यमंत्री प्रचार नहीं करते हें लेकिन दो सीटों के उपचुनाव में सिद्धारमैया ने जम कर प्रचार किया. कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत गई.

चुनाव से पहले बाहरी भाजपा नेताओं की आहट

राजनीतिक मिजाज भी भांपने कई चारधाम यात्रा के बहाने भी पहुंचेंगे

देहरादून. पांच राज्यों में चुनाव के बाद अब भाजपा ने उत्तराखंड में चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. राज्य स्तर के दो सर्वे के अलावा केंद्रीय नेतृत्व के स्तर से भी राज्य में लगातार तीसरी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है.

दूसरे राज्यों के नेताओं की उत्तराखंड में आहट होने लगी है, जो कि धीरे-धीरे और बढ़ेगी. भाजपा ने उत्तराखंड के नेता-कार्यकर्ताओं को तीन राज्यों में प्रचार में लगाया था. इनमें कैबिनेट मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने तो करीब एक साल तक वहां काम किया. वहीं, युवा मोर्चा समेत कई अन्य पदधिकारियों को पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भेजा गया था. राजस्थान के विधायकों का पूरा दल बंगाल चुनाव में भेजा गया था.

Uttarakhand

कई अन्य राज्यों के सांसद, मंत्री, विधायक इन राज्यों में जुटे थे.

अब अगली तैयारी उत्तराखंड के चुनाव की है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में कई राज्यों के नेता व कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं. कई ऐसे भी हैं जो कि चारधाम यात्रा करेंगे और प्रदेश का राजनीतिक मिजाज भी भांपकर जाएंगे. केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से भी प्रदेश में अलग सर्वे कराएगा. इससे तस्वीर और साफ हो सकेगी. केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर से भी विधायकों की परफॉर्मेंस चेक करा रहा है.

> **बूथ मैनेजमेंट में उत्तराखंड की छवि मजबूत**
>
> बूथ मैनेजमेंट में उत्तराखंड की छवि काफी मजबूत है. पांच राज्यों के चुनाव से पहले भी प्रदेश के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अलग-अलग राज्यों के चुनाव में भेजा जाता रहा है. इसी प्रकार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के संगठन पदधिकारियों का भी अलग काम करने का तरीका है. इसी हिसाब से पार्टी यहां उनका इस्तेमाल करेगी.

सपा ने क्यों छोड़ा आईपैक का साथ ?

लखनऊ. समाजवादी पार्टी ने चुनाव रणनीति बनाने और चुनाव प्रबंधन करने वाली एजेंसी आईपैक के साथ करार खत्म कर लिया है. कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने आईपैक से करार किया है.

ध्यान रहे आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने 2012 का गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने में भाजपा और नरेंद्र मोदी की मदद की थी और फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाने और प्रबंधन का काम किया था. उसके बाद उनके पूरे देश ने जाना. उन्होंने कई राज्यों में नेताओं के लिए काम किया.

ममता बनर्जी को पिछला चुनाव उन्होंने लड़वाया था. लेकिन अब प्रशांत किशोर आईपैक से अलग हो गए हैं और अपनी राजनीति कर रहे हैं.

प्रशांत किशोर के हटने के बाद प्रतीक जैन, विनेश चंदेल, ऋषिराज सिंह आदि आईपैक का संचालन करते हैं. यह टीम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का चुनाव संभाल रही थी.

> कहा जा रहा है कि बंगाल में ममता की हार के बाद अखिलेश यादव ने आईपैक से करार तोड़ लिया है. लेकिन इसका असर कारण पश्चिम बंगाल का फैसला नहीं है, बल्कि एजेंसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई है. असल में चुनाव से पहले जनवरी में ईडी ने आईपैक पर छापा मारा. ईडी ने कहा कि कोयला तस्करी का पैसा आईपैक के जरिए काले से सफेद किया गया है. उस समय इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ. बाद में ईडी ने चुनाव प्रचार के बीच छापा मारा और एक निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी ने इसके बाद ऋषिराज सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया. ईडी के चक्कर में आईपैक ने काम ही बंद कर दिया. बीच चुनाव में ममता बनर्जी की रणनीति का काम बंद हो गया. अखिलेश यादव ने इसी डर से आईपैक को छोड़ा. उनको लगा कि अगर चुनाव के बीच ईडी कार्रवाई करे, कंपनी के निदेशकों को गिरफ्तार करे और उनका कार्यालय बंद हो तब चुनाव पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगा. उन्होंने आईपैक के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से नहीं, बल्कि ईडी की चिंता में आईपैक का साथ छोड़ा है.

विशेष बंगाल जैसा रहा हाल तो बंद हो जाएंगी राजनीति की खिड़कियां

विपक्ष के सामने अस्तित्व की चुनौती

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.जिस बंगाल को कभी बीजेपी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक जमीन माना जाता था, वहां जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर है. लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को रोका कैसे जाए? क्योंकि बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की एकता, नेतृत्व और रणनीति तीनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

बंगाल में बीजेपी की जीत ने यह साफ कर दिया है कि अब पार्टी सिर्फ हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं रही. बीजेपी ने बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी की राजनीति को हिंदुत्व और वेलफेयर के बड़े नैरेटिव से काउंटर किया. मुफ्त योजनाएं, मजबूत संगठन और हिंदुत्व की भावनात्मक राजनीति इस तिकड़ी ने बीजेपी को बंगाल में ऐतिहासिक बढ़त दिलाई. सबसे बड़ा संदेश यह गया कि भाषा और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर भी एक राजनीतिक पहचान तैयार की जा सकती है. यानी जिस तरह बंगाल में हिंदुत्व ने अपनी जगह बनाई, उसी तरह दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर भी बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है. उस आत्मविश्वास के जवाब में अब विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा होता दिख रहा है. राहुल गांधी ने उनसे बात कर 'वोट चोरी' का आरोप उठाया, वहीं अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचकर ममता से मिले और कहा कि दीदी, आप हारी नहीं हैं.लेकिन पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत वोट प्रतिशत में साफ दिखाई देती है. बीजेपी को 45.84 प्रतिशत वोट मिले, जबकि टीएमसी को 40.80 प्रतिशत. सीपीएम को 4.45 प्रतिशत, सीपीआई-आरएसपी समेत अन्य वाम दलों को करीब 1 प्रतिशत और कांग्रेस को 2.97 प्रतिशत वोट मिले.

> **'वोट बंटवारे' बनाम 'वोट चोरी' की राजनीति'**
>
> इंडिया गठबंधन खुद 'एकता में अनेकता' का प्रतीक है. कई राज्यों में इसके सहयोगी दल एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं. ऐसे में विपक्ष अब 'वोट बंटवारे' बनाम 'वोट चोरी' की राजनीतिक लाइन पर खड़ा दिख रहा है और यही नैरेटिव आगे भी चलाया जाएगा कि 'जहां-जहां एसआईआर हुआ, वहां-वहां विपक्ष हारा. खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी पहले से मजबूत संगठनात्मक आधार रखती है. लेकिन पश्चिम बंगाल का गणित विपक्षी दलों के लिए एक राजनीतिक अलार्म भी है. आने वाले चुनावों में यूपी, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी दलों को आपसी फूट से ऊपर उठकर सोचना होगा. क्योंकि अगर विपक्षी वोट इसी तरह अलग-अलग खेमों में बंटता रहा, तो कई राज्यों में बीजेपी को सीधा फायदा मिलता रहेगा भले ही कुल विपक्षी वोट प्रतिशत उससे ज्यादा क्यों न हो.